

भारत सरकार  
जल शक्ति मंत्रालय  
जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग  
लोक सभा  
अतारांकित प्रश्न संख्या 1841  
दिनांक 31 जुलाई, 2025 को उत्तरार्थ

.....

जल संसाधनों का सतत प्रबंधन

1841. श्रीमती माला राज्यलक्ष्मी शाह:

श्री भर्तृहरि महताबः

श्री प्रभुभाई नागरभाई वसावाः

श्री जशुभाई भिलुभाई राठवाः

श्री विजय कुमार दूबेः

श्री बसवराज बोम्मईः

श्री बलभद्र माझीः

श्री बिभु प्रसाद तराईः

श्री जनार्दन मिश्राः

श्री गोडम नागेशः

क्या जल शक्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार ने हिमालयी क्षेत्र में हिमनदों और हिमनद झीलों की निगरानी के लिए रणनीतिक कार्रवाई की है;
- (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है;
- (ग) क्या भारत के जल संसाधनों के सतत प्रबंधन के लिए डेटा-आधारित नीति निर्माण में सहायता करने के लिए कोई कदम उठाए गए हैं; और
- (घ) यदि हां, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है?

उत्तर

जल शक्ति राज्य मंत्री

(श्री राज भूषण चौधरी)

(क) और (ख): सरकार ने विभिन्न मंत्रालयों, विभागों और संस्थानों के माध्यम से भारतीय हिमालयी क्षेत्र (आईएचआर) में ग्लेशियरों और हिमनद झीलों की निगरानी के लिए रणनीतिक और व्यवस्थित कार्रवाई की है।

जल शक्ति मंत्रालय ने हिमालयी ग्लेशियरों पर विभिन्न मंत्रालयों और संगठनों द्वारा किए गए कार्यों की निगरानी और समन्वय के लिए जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग के सचिव की अध्यक्षता में 'ग्लेशियर की निगरानी' पर एक संचालन समिति का गठन किया है।

जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत केंद्रीय जल आयोग (सीडब्ल्यूसी) भारत में हिमनद झीलों और जल निकायों की निगरानी करने के लिए नोडल एजेंसी है। सीडब्ल्यूसी वर्तमान में भारतीय नदी घाटियों के हिमालयी क्षेत्र में राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र (एनआरएससी) द्वारा तैयार की गई ग्लेशियल झील सूची 2011 में शामिल 10 हेक्टेयर से बड़े आकार के 902 ग्लेशियल झीलों और जल निकायों (जीएल एंड डब्ल्यूबी) की निगरानी, प्रत्येक वर्ष जून से अक्टूबर की अवधि के लिए, रिमोट सेंसिंग तकनीकों के उपयोग द्वारा करता है। गृह मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) राष्ट्रीय हिमनद झील विस्फोट बाढ़ (जीएलओएफ) जोखिम शमन कार्यक्रम (एनजीआरएमपी) के तहत ग्लेशियरों और ग्लेशियल झीलों की निगरानी भी करता है, जिसे चार हिमालयी राज्यों, नामतः - हिमाचल प्रदेश, उत्तराखण्ड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में लागू किया गया है।

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग (डीएसटी) के अंतर्गत वाडिया हिमालयन भूविज्ञान संस्थान (डब्ल्यूआईएचजी) मध्य हिमालय, पश्चिमी हिमालय और काराकोरम क्षेत्रों में फील्ड-आधारित अवलोकनों के माध्यम से ग्लेशियरों की सक्रिय निगरानी करता है। वर्तमान में, डब्ल्यूआईएचजी तेरह ग्लेशियरों की निगरानी कर रहा है, जिनमें से सात मध्य हिमालय में और छः पश्चिमी हिमालय तथा काराकोरम में हैं।

खान मंत्रालय के अंतर्गत भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (जीएसआई) भी ग्लेशियरों के घटने या बढ़ने की निगरानी और मापन तथा विशेष रूप से भारतीय हिमालयी क्षेत्र में चुनिंदा ग्लेशियरों के द्रव्यमान संतुलन अवलोकनों का संचालन करता है।

जी. बी. पंत राष्ट्रीय हिमालयी पर्यावरण संस्थान (जीबीपीएनआईएचई), जो पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफ एवं सीसी) का एक स्वायत्त संस्थान है, भी क्षेत्र मापन और सुदूर संवेदन पद्धति द्वारा हिमालयी क्षेत्र में ग्लेशियरों के अध्ययन में शामिल है।

पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय (एमओईएस) अपने स्वायत्त संस्थान, राष्ट्रीय ध्रुवीय एवं महासागर अनुसंधान केंद्र (एनसीपीओआर) के माध्यम से पश्चिमी हिमालय में चंद्रा बेसिन (2437 वर्ग किमी क्षेत्र) में छह ग्लेशियरों की निगरानी करता है।

भारतीय हिमालयी क्षेत्र (आईएचआर) के जल संसाधनों पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव का अध्ययन करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान (एनआईएच), रुड़की में क्रायोस्फीयर और जलवायु परिवर्तन अध्ययन केंद्र की स्थापना की गई है।

**(ग) और (घ):** जल शक्ति मंत्रालय ने भारत के जल संसाधनों के सतत प्रबंधन हेतु डेटा-संचालित दृष्टिकोण को सक्षम बनाने हेतु विभिन्न पहल की हैं। इन प्रयासों का उद्देश्य जल-संबंधी डेटा की उपलब्धता, गुणवत्ता और पहुँच में सुधार लाना है, जिससे वैज्ञानिक नियोजन, कुशल संसाधन आवंटन और प्रभावी निर्णय लेने में सहायता मिल सके।

राष्ट्रीय जल विज्ञान परियोजना (एनएचपी) विश्व बैंक द्वारा समर्थित एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है, जिसमें राज्य/केंद्रीय कार्यान्वयन एजेंसियाँ शामिल हैं। एनएचपी के पास अखिल भारतीय कवरेज है जिसमें केंद्र सरकार और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की 48 कार्यान्वयन एजेंसियाँ शामिल हैं, जिसका उद्देश्य जल संसाधन सूचना की सीमा और पहुँच में सुधार करना और बाढ़ प्रबंधन, जल संसाधन मूल्यांकन और योजना के लिए निर्णय समर्थन प्रणाली बनाना है।

राष्ट्रीय जल सूचना विज्ञान केंद्र (एनडब्ल्यूआईसी) की स्थापना भारत सरकार द्वारा जल ऑकड़ों और संबद्ध विषयों के केंद्रीय संग्राहक के रूप में कार्य करने के लिए की गई थी। यह विभिन्न हितधारकों द्वारा उपयोग हेतु जल ऑकड़ों और सूचनाओं का संग्रह, रखरखाव, अद्यतन और प्रसार करता है। एनडब्ल्यूआईसी बेहतर अंतर-मंत्रालयी समन्वय और स्थानिक नियोजन हेतु जीआईएस-आधारित उपकरणों का उपयोग करते हुए जल संसाधन नियोजन को पीएम गति शक्ति के साथ भी संरेखित कर रहा है।

केंद्रीय भूजल बोर्ड (सीजीडब्ल्यूबी) द्वारा शुरू किए गए राष्ट्रीय जलभूत मानचित्रण और प्रबंधन (नेक्यूम) कार्यक्रम का उद्देश्य वैज्ञानिक ऑकड़ों का उपयोग करके स्थायी भूजल प्रबंधन हेतु पूरे भारत में जलभूतों का चित्रण और उनकी विशेषताओं का वर्णन करना है।

देश के प्रमुख जलाशयों में जल भंडारण की निगरानी के लिए केंद्रीय जल आयोग (सीडब्ल्यूसी) द्वारा जलाशय भंडारण निगरानी प्रणाली विकसित की गई है। जल भंडारण ऑकड़ों की साप्ताहिक बुलेटिन को, नियोजन करने के लिए और सूचित जल निर्गमन निर्णयों के लिए हितधारकों के साथ साझा किया जाता है।

\*\*\*\*\*